

अमेरिका से भारत भेजे गये प्रत्येक 1000 डॉलर पर अब पचास डॉलर का नया टैक्स लगेगा

जैसा कि विदित ही है, अमेरिका से भारतीय मूल के 45 लाख लोग, अपने वृद्ध माँ-बाप के लिये, बच्चों की शिक्षा व अन्य इमरजेंसियों के लिए, प्रति वर्ष लगभग 100 बिलियन डॉलर भेजते हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 मई। अमेरिकी प्रशासन के एक नए लैजिस्लेटिव प्रपोज़ल (विधायी प्रस्ताव) ने अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों और नई दिल्ली के नीति निर्धारकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। “वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट” नाम के इस प्रस्ताव में अमेरिका से विदेश भेजी जाने वाली रकम पर 5 प्रतिशत एक्साइज टैक्स लगाने की बात कही गई है, यह कदम भारतीय प्रवासी और उनके देश में बसे परिवारों के बीच की एक महत्वपूर्ण फायनैशियल लाइफलाइन को झटका दे सकता है। यदि यह कानून बनता है, तो इसका असर भारत के शहरों से लेकर गांवों तक के घरेलू बजटों पर पड़ेगा और भारत की व्यापक आर्थिक प्रणाली तक पहुँचेगा। यह प्रस्तावित टैक्स सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों द्वारा अपने देशों में भेजी जाने वाली राशि पर लागू होगा, (शेष पृष्ठ 5 पर)

- अब इस 5 प्रतिशत के नये प्रस्तावित टैक्स से, इस रकम में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की कमी होने का अंदाज़ा है।
- गाँव व छोटे-छोटे शहरों में बसे परिवारों के लिए अमेरिका से उनके बच्चों द्वारा भेजी गई यह रकम जीवन-दायिनी का काम करती थीं। अतः अमेरिका से आने वाले पैसे की “फ्रीक्वेंसी” कम हो जायेगी या “अमाउंट” कम हो जाएगा।
- अतः, भारी संभावना है कि अब अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीय, अपने परिवार को भेजने वाले पैसे को हवाला या अन्य “अव्यवस्थित व गैर कानूनी” रास्ते से भेजने लगेंगे।
- भारत में विदेश से (अमेरिका से) आने वाली रकम घटने से भारत का विदेशी मुद्रा का कोष (रिज़र्व) भी लगातार कम होगा।
- साथ ही भारत व अमेरिका के बीच संबंधों में दरार भी आ सकती है, क्योंकि ये अप्रवासी भारतीय अपनी मेहनत से अमेरिका की इकॉनमी को समृद्ध तो करते ही हैं, अपने भारत स्थित परिवारों का लालन-पालन भी करते हैं और उनकी इस जायज आय को बाधित करने से दोनों देशों के बीच तनाव तो आयेगा ही।
- पर, ट्रम्प इस कदम से अपने वोट बैंक को तो खुश कर रहे हैं, जो कि “अमेरिका फर्स्ट” नारे में विश्वास करते हैं तथा भारी संख्या में विदेशियों के अमेरिका आने को पसंद नहीं करते।

सुप्रीम कोर्ट ने अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी को जमानत पर रिहा किया

पर, साथ ही कटाक्ष भी किया कि जब देश युद्ध में फंसा है तथा दुष्ट सड़कों पर घूम रहे हैं, तब हमें संगठित रहना चाहिए या सस्ती लोकप्रियता की फिराक में “सांप्रदायिक टिप्पणियाँ” करनी चाहिये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत दे दी, जिन्हें 18 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर विवादकल्पद पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जॉच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। प्रोफेसर को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत तो दी, पर ऑपरेशन सिंदूर को “डॉंग विसर्लिंग” और “सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास” बताने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

बाटा ने कैरी बैग के 6 रु. वसूले, 61 हजार का जुर्माना भरना पड़ा

जयपुर, 21 मई। जिला उपभोक्ता आयोग, तृतीय ने ग्राहक को जूती के साथ कंपनी का नाम लिखा कैरी बैग देने के बदले 6 रुपए वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष माना है। इसके साथ ही, आयोग ने बाटा इंडिया पर 61 हजार रुपए हर्जाना लगाते हुए उसे निर्देश दिया है कि वह परिवादी से कैरी बैग के लिए वसूले 6 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज

- **जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा, कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन है, इसलिए वह निःशुल्क होना चाहिए।**

सहित लौटाए। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीना पारीक के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निःशुल्क होना चाहिए था। मामले के अनुसार परिवादी ने 27 फरवरी, 2024 को विश्वेश के शु स्टोर से एक जोड़ी जूता व एक जोड़ी स्लीपर 4698 रुपए में खरीदे, लेकिन विपक्षी (शेष पृष्ठ 5 पर)

- **सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर के खिलाफ जॉच जारी रखने की भी इजाजत दी तथा प्रोफेसर का पासपोर्ट भी सरकार में जमा कराने का आदेश भी दिया।**
- कोर्ट ने निर्देश दिए कि वे पहलगाम टेरर अटैक के संबंध में और भारत-पाक शत्रुता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया। महमूदाबाद को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और हरियाणा की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की
- बीकानेर, (कासं) 21 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को बीकानेर आयेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का राजस्थान का यह पहला दौरा है। कहा जा रहा है कि मोदी नाल एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री देशनोक में करणी माता के दर्शन करेंगे और देशनोक में ही आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वे पलाना (देशनोक) में सभा को संबोधित करेंगे। मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर बैनर और होर्डिंग लगाये गए हैं। राजस्थान के चीफ सैफ्रेटरी सुधांशु पंत ने बुधवार को पलाना में सभा स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के अपने दौर में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी अवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे, जहां, आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी। वहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी।

न्यायिक हिरासत में भेजा था। उनकी पोस्टको सेना के लिए निंदनीय और महिला सैन्य अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग की थी, के प्रति अपमानजनक माना गया। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने की थी। जस्टिस कांत ने कहा, “सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन क्या यह समय है, इतनी ज्यादा सांप्रदायिकता पर बात करने का.....? देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है। राक्षसों ने निर्दोशों को जानें लीं। हम सभी एकजुट थे, पर ऐसे मौके पर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश क्यों?

- **हार्डकोर्ट ने गुहसचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर व जामडोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।**

ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता एसएस अली ने अदालत को बताया कि गत 5 मई को याचिकाकर्ता के घर कुछ पुलिसकर्मी आए और उसकी मां साजिदा को बिना कारण बताए अपने साथ ले गए। याचिकाकर्ता ने जामडोली थाने में कई बार (शेष पृष्ठ 5 पर)

अवैध बांग्लादेशी बता कर महिला को हिरासत में लेने का मामला

जयपुर, 21 मई। राजस्थान हार्डकोर्ट ने जामडोली थाना इलाके में रहने वाली महिला को कथित रूप से अवैध बांग्लादेशी बताकर उसे हिरासत में लेने के मामले में गुह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और जामडोली थानाधिकारी सहित, अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश शोएव की

पहलगाम की घटना ने हमारे लिये “वेक अप” कॉल का काम भी किया

हालांकि, पहलगाम को अंजाम देने वाले आतंकवादी अभी पकड़े नहीं गये हैं, पर, सघन “इंटेलिजेंस कार्यवाही” से, “स्पाय रिंग” का पर्दाफाश हुआ, जो देश भर में फैली हुई थी तथा जासूस पाकिस्तान में अपने “हैंडलर्स” से लगातार सम्पर्क में थे

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 21 मई। अभी हाल ही में हुई हरियाणा-निवासी एक यूट्यूबर तथा उसके कई सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद, भारत में एक बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क के सामने आने से देश की गुप्तचर एजेंसियों की खामियों को लेकर गहन चिन्ता पैदा हो गई है। गुप्तचर एजेंसियों की कार्यक्षमता की यह चूक पहलगाम नरसंहार के बाद ही चर्चा में आ गई थी। ज्ञातव्य है कि पहलगाम में चार अज्ञात हमलावरों ने इस घातक हमले को अंजाम दिया था, लेकिन वे अभी तक इन एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में संबंधित जासूसी कृत्य से जुड़े 11 लोग गिरफ्तार किये गये हैं। इनमें हिसार-निवासी व्त्नोअर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है, जिसके बारे में यह माना

- **हिसार की ज्योति मल्होत्रा इस “रिंग” की मुखिया की तरह काम कर रही थी तथा ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने भारत के “इंटेलिजेंस” की आँखें भी खोलीं, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े “स्पाय रिंग” के सक्रिय होने की जानकारी कभी नहीं मिली, इसीलिए भीड़ में चारों आतंकवादी बाहर निकल गये। अगर पहलगाम की घटना नहीं होती तो हमारी “इंटेलिजेंस” एजेंसियां अपने निवास में आसम से सोती रहती और “स्पाय रिंग” निर्बाध रूप से दस साल और चलती रहती।**

जा रहा है कि संवेदनशील सूचनाएं जुटाने तथा उन्हें पाकिस्तान स्थित हैन्डलर्स तक पहुंचाने में उसकी केन्द्रीय भूमिका थी। मल्होत्रा, जो इस समय पुलिस कस्टडी में है, को उन सभी स्थानों पर ले जाया जा रहा है, जहां वह पिछले वर्ष में गई थी। ऐसा संदेह है कि इन स्थानों पर उसने विदेशी संचालकों एवं आकाओं के

निर्देशानुसार, विभिन्न प्रकार के सर्वे किये हैं तथा सैन्य जासूसी की है। गुह मंत्रालय ने इस कार्यवाही को खुफिया गतिविधियों के विफल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ एवं पुराने अधिकारी इससे कम ही सहमत हैं। उनका कहना है कि इस जासूसी नेटवर्क

का भण्डाफोड़ वस्तुतः गहरे तन्त्रगत मुद्दों एवं दोनों की ओर संकेत करता है, खासतौर से इस बात की विफलता, कि पहलगाम हत्याकांड को समय रहते रोक़ा क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके समय रहते पता चलने से और ज्यादा आक्रामक काउन्टरइन्टेलिजेंस रेस्पॉन्स दिया जा सकता था। एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी ने, नाम न छापने की शर्त पर, कहा, “अगर पहलगाम की घटना न हुई होती, तो यह नेटवर्क कई महीनों, बल्कि सालों तक हमारी नजरों में नहीं आया होता। इस घटना ने एक उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) काम किया है। लेकिन इससे यह भी उजागर हो गया कि हम किस हद तक गैर-मुस्तैद थे। पहलगाम की घटना में लिप्त चार हमलावरों की पहचान तथा गिरफ्तारी न (शेष पृष्ठ 5 पर)

विधायक कंवर लाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेन्डर किया

जयपुर, 21 मई। भाजपा के अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने करीब एक माह से जारी लंबी जद्दोजहद के बाद, आखिरकार बुधवार को मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पूर्व कंवर लाल मीणा ने प्रसिद्ध तीर्थ कामखेड़ा बालाजी मंदिर के दर्शन किए और बालाजी का आशीर्वाद लिया। विधायक मीणा को सुप्रीम कोर्ट ने

- **सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की याचिका खारिज कर दो सप्ताह में कोर्ट में सरेन्डर करने का आदेश दिया था।**

उनकी लगाई याचिका खारिज होने के बाद, दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश जारी किए थे। गौरतलब है कि विधायक कंवरलाल मीणा पर 20 वर्ष पूर्व चुनाव अधिकारी पर पिस्टल तानकर धमकाने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा था। इसके बाद एडीजे कोर्ट अकलेरा की ओर से विधायक मीणा को (शेष पृष्ठ 5 पर)